नगर निगम को लूट की जागीर मान कर

कमीशनखोरी के लिये खरीदा था लाखों का लोहा खुल्लर ने

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिये अथवा सीवर के मैनहोल ढकने या सड़कों के गड्ढे भरने के लिये पैसा हो या न हो परन्तु मोटे कमीशन के लिये लाखों करोड़ों की खरीददारी करने में निगम अधिकारियों को कोई परहेज नहीं।

एनआईटी नम्बर 2 स्थित तिकोना पार्क मार्केट के पीछे नगर निगम का एक भूखंड है जिसमें पानी के भूमिगत टैंक बने हैं। करीब 2 एकड़ के इस भूखंड के एक तरफ़ सरकारी स्कूल व दूसरी तरफ़ नाहर सिंह स्टेडियम है। इस भूखंड पर गत लगभग दसियों वर्ष से लोहे के सैंकड़ों टन जंगले पड़े हैं। ये जंगले सड़कों के डिवाइडरों पर लगाने के नाम पर खरीदे गये थे। डिवाइडरों पर न तो इनकी जरूरत थी और न ही ये लगे। खरीदने थे बस खरीद लिये। पमेंट कर के मोटा कमीशन डकार लिया गया और जंगले इस प्लॉट में भर दिये गये। गत दसियों बरस में स्वत: उगे पेड़ पौधों व घास आदि ने इन जंगलों को पूरी तरह से

ढक लिया है। विशेष ध्यान देने व टोह लेने पर ही इन्हें देखा जा सकता है। इस लम्बे अन्तराल में पड़ी मौसम की मार से इन जंगलों की हालत वैसे भी खस्ता हो चुकी है जो शायद ही किसी काम आने लायक बचे हों।

जानकार सूत्रों का मानना है कि यह खरीद खुल्लर ने बतौर निगमायुक्त की थी। लोहे के उक्त जंगले बनानेवाला भी कोई उनका निकट सम्बन्धी ही बताया गया है। यह वह समय था जब तिकोना पार्क से लेकर ईएसआई अस्पताल डीएवी कॉलेज होते हुए चिमनीबाई धर्मशाला के निकट के चौक तक जाने वाली सड़क को डबल किया जाना था। डबल होने वाली इस सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगाने के नाम पर सड़क बनने से पहले ही खुल्लर ने ये जंगले खरीद डाले थे।

सुधी पाठकों को याद होगा कि उसी सड़क का काम पूरा कराने के नाम पर तत्कालीन मन्त्री महेन्द्रप्रताप ने गुड़गांव नगर निगम से 100 करोड़ रुपया फ़रीदाबाद नगर निगम को उधार दिलाये थे। यानी सड़क बनाने के पैसे तो थे नहीं उसमें लगाने के लिये जंगले पहले से खरीद लिये गये। यही नहीं खरीददारी करने के शौक एवं कमीशनखोरी के चक्कर में खुल्लर ने कूड़ा ढोने के लिये दर्जनों छोटे ट्रक भी खरीद डाले थे। जितनी पेमेंट निगम के खजाने में उपलब्ध थी वह तो खुल्लर ने हाथों-हाथ कर दी, शेष उधार खाते में आने वाले निगमायुक्तों के लिये छोड़ दी। यानी जो खरीदारी खुल्लर साहब कर गये उसकी अदायगी उनके बाद आने वाले आयुक्त करते रहें। खरीदारी तो खुल्लर की लूट कमाई का एक बहुत छोटा सा साधन था। उनकी असल लूट कमाई तमाम निर्माण कार्यों के ठेकों, अवैध निर्माणों, अवैध कब्ज़ों व तोड़-फ़ोड़ की धमकी से होती थी। विवादित नक्शे पास कराना, सीएलयू कराना तथा कोर्ट केसों में सौदे करना उनके लिये आम बात थी। वैसे तो इस नगर निगम में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी तैनात रह चुके हैं, परन्तु खुल्लर जैसे 'समझदार' के मुकाबले ठहरने वाला कोई नज़र नहीं आया।

जब हरियाणा में इनकी दाल गलनी बंद हो गयी और मलाईदार की जगह बंजर तैनातियां मिलने लगी तो खुल्लर ने हरियाणा छोड़ कर केन्द्र सरकार की सेवा का रूख किया। लेकिन शीघ्र ही बिल्ली के भागों छीका टुट गया। हरियाणा में खट्टर सरकार आ गयी। खट्टर अपने बिरादरी भाइयों को ढूंढ-ढूंढ कर मलाईदार तैनातियां देने में लग गये। इसका भरपूर लाभ उठाते हुए खुल्लर साहब पुन: हरियाणा लौट आये। कुछ दिन तो खट्टर के दांये-बांये घूमे और शीघ्र ही खट्टर के प्रधान सचिव जैसा मलाईदार पद हथिया लिया। इस पद पर तैनात अ.फ़सर मुख्यमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह जो भी कुछ करता या कहता है उसे मुख्यमंत्री का आदेश समझा जाता है।

ऐसे में जब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहेगी तो पूरे राज्य भर की सिंचाई तो ठीक से हो ही जायेगी।

कृष्णपाल से काम नहीं चला तो दो मन्त्री और आये मोदी गान करने

फ़रीदाबाद (म.मो.) हज़ारों करोड़ विज्ञापनबाज़ी पर खर्च करने के बावजूद लोग़ों को बहकावे में न आता देख प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपने तमाम सांसदों व मन्त्रियों कों शहर-शहर, गांव-गांव घूम कर भाजपाई मोदी सरकार का यशोगान करने के आदेश जारी किये हैं। भाजपा यह मान कर चल रही है कि उनकी मोदी सरकार ने अपने 2 वर्ष के शासन में जनता को जो दिया है, देश को जितना आगे बढाया है, लोग़ों को उसका पता ही नहीं।

फ़रीदाबाद से निर्वाचित भाजपाई सांसद एवं केन्द्र सरकार में मन्त्री कृष्णपाल ने पिछले 2 साल में मोदी का यशोगान करने के अलावा कुछ भी तो नहीं किया। आये दिन किसी न किसी गली में नारियल फ़ोड़ना, झूठी लफ़्फ़ाजी करना, मैट्रो रेल गुड़गांव, पलवल तथा नहर पार चलाना आदि इनकी विशेष 'उपलब्धि' रही है। इनकी सबसे बड़ी 'उपलब्धि' 15 अगस्त 2014 को यमुना पुल का शिलान्यास कराने के लिये केन्द्रीय सड़क मन्त्री गडकरी को बुलाना भी रही है। इस तरह की लफ़्फ़ाजियों से जनता को आखिर कब तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है?

कृष्णपाल के इस 'पुनीत' कार्य में सहयोग देने के लिये भाजपा नेतृत्व ने दिनांक 7 जून को दो केन्द्रीय मंत्री-राधा मोहन व बाबुल को भी फ़रीदाबाद भेजा। कृष्णपाल व अन्य स्थानीय नेताओं के साथ मिल कर उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया। इसमें बताया गया कि मोदी सरकार ने गत 2 वर्ष में करोड़ों जन-धन खाते खोल दिये, गैस कनेक्शन बांट दिये स्वच्छता अभियान चला दिया आदि-आदि। यानी सब हवा-हवाई बातें उन्होंने की। पत्रकार कोई ढंग के सवाल न पूछ पाये, इसका पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। अव्वल तो बड़ी सीमित मात्रा में ही पत्रकारों को बुलाया गया था। उनमें से भी कुछेक को तयशुदा प्रश्न पूछने के लिये तैयार कर लिया गया था। इसके बावजूद भी दोनों मन्त्री शीघ्रता से निकल लिये ताकि कोई और ढंग का प्रश्न न पूछ ले।

'मज़दूर मोर्चा' ने भरसक प्रयास किया है, इन नेताओं को समझाने का कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना वे समझते हैं। जनता झूठे प्रचारतंत्र की अपेक्षा धरातल पर देखती है कि सरकार ने क्या कुछ किया है और उसे वास्तव में मिल क्या रहा है। विज्ञापनबाज़ी पर खर्च किया गया लाखों करोड़ रुपया जनता को वह बात नहीं समझा सकता जो धरातल पर किया गया काम बोलता है। परन्तु तमाम पाखंडी नेता इस सच्चाई को समझने की मानसिक स्थिति में नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग, जो पूर्णतया केन्द्र सरकार के आधीन है, गत लगभग 3 वर्षों से शहर की जनता के लिये मुसीबत बना हुआ है। भाजपा से पहले कांग्रेसी सरकार ने इसका काम रिलायंस कम्पनी को, मैट्रो रेल से पहले सौंपा था। मैट्रो रेल बनकर कब की चालू हो गयी, लेकिन राजमार्ग के दुरूस्त होने के अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जुमलेबाज़ी में माहिर भाजपाई यदा-कदा घोषणायें जरूर करते रहते हैं कि पी एम ओ अब सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा है, अब यह हो जायेगा, तब यह हो जायेगा आदि-आदि। परन्तु रिलायंस के मालिक अनिल अम्बानी की सेहत पर कतई कोई असर नहीं। वह टोल टैक्स खा-खा कर मोटा हुआ जा रहा है और जनता उसे भुगतने को अभिशप्त है।

रेलवे सीधे मोदी सरकार के आधीन है। इन 2 वर्षों में यहां के नागरिकों को रेल सेवा में रत्ती भर सुधार देखने को नहीं मिला। इस रूट पर बढते रेल यातायात के लिये अतिरिक्त (चौथी) लाइन व स्टेशन बिल्डिंग बनाने का काम जहां 2 साल पहले खड़ा था, वहीं आज खड़ा है। गेहूं की सरकारी खरीद केन्द्र व राज्य सरकार की एजेंसियां मिल कर करती हैं। इस काम में भी इन्होंने जनता, खास कर किसानों को रूला दिया। पहले तो समय पर खरीद नहीं हुई, हो गयी तो उसे उठाने का प्रबन्ध नहीं, मंडियों में पड़ा गेहूं कभी आग से जल गया तो कभी बारिश में भीग-भीग कर गल गया।

हरियाणा के करीब 18 लाख मज़दूरों से प्रति वर्ष करीब 1100-1200 करोड़ रुपया ईएसआई कार्पोरेशन वसूल तो कर लेती है, परन्तु बदले में चिकित्सा सेवा देने में दोनों सरकारें पूरी तरह से नाकाम हैं। मज़दूरों का हज़ारों करोड़ रुपया ईएसआईसी के खजाने में सड़ रहा है, परन्तु इसके अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में न तो पर्याप्त स्टाफ़ है और न ही आवश्यक उपकरण आदि। ऐसे में मज़दूर को रंग बिरंगे विज्ञापनों से सरकार कब तक भ्रमित करेगी? स्वच्छता अभियान के नाम पर फ़ोटो सेशन चला कर सरकार ने जनता पर स्वच्छता टैक्स तो थोप दिया लेकिन इस अभियान से स्वच्छता नदारद है, केवल अभियान ही रह गया। टैक्स पर टैक्स व महंगाई लगातार बढ़ती हर नागरिक को बखूबी दिख रही है। झूठे प्रचारतन्त्र से उसकी आंखों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।

सांठ-गांठ के लिये चहेता थानेदार चाहिये विधायकों को

फ़रीदाबाद (म.मो.) पृथला के विधायक टेक चंद शर्मा व बल्लबगढ़ के विधायक मूल चन्द शर्मा को छायंसा का एसएचओ प्रीतपाल सांगवान माफ़िक नहीं आ रहा था क्योंकि वह उनकी सांठ-गांठ में शामिल होने से साफ़ इन्कार कर देता था। इसके चलते दोनों विधायकों की दुकानदारी काफ़ी मंदी चल रही थी। परेशान दोनों विधायकों ने मिल कर ज़ोर लगाया और अपनी पसंद का बल्कि देखा-परखा एसएचओ महेन्द्र शर्मा को पलवल से तबादला करा कर ले आये और उसे छांयसा में लगवा लिया।

वैसे ऊपरीतौर पर देखने से इस तबादले में जातीय रंग भी नज़र आता है। एक जाट की जगह दोनों विधायक अपने बिरादरी भाई को बतौर एसएचओ ले आये। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि प्रीतपाल उनके इशारों पर नाचता व उनके उल्टे-पुल्टे काम करके उनकी दुकानदारी चलवाता रहता तो वह बहुत बढिया हो जाता, फ़िर उन्हें जाट से कोई परहेज न होता। उधर महेन्द्र शर्मा भी यदि प्रीतपाल की तरह ही सीधे रास्ते चलने वाला होता तो उसका शर्मा होना भी इनके लिये बेकार था। लेकिन महेन्द्र शर्मा इनका पहले से देखा-परखा इन्सपेक्टर था।

जून 2015 में महेन्द्र शर्मा की तैनाती बतौर एसएचओ सेक्टर 7 थी। उस वक्त सेक्टर 9 की कोठी नम्बर 67 का एक मामला चल रहा था। इस कोठी पर मूल चन्द विधायक के भाई टिप्पर चंद के सहयोग से बडौली के दो चंदीला भाइयों ने कब्ज़ा कर रखा था। जांच करने वाले सब-इन्स्पेक्टर जगबीर ने एसएचओ व टिप्पर चंद की परवाह न करते हुए जब सच्ची रिपोर्ट तैयार कर दी तो उस रिपोर्ट को दबवाने के लिये एक एएसआई की जांच रिपोर्ट ऊपर लगा दी थी। 'मज़दूर मोर्चा' के 1-15 अक्तूबर 2015 में 'पुलिस-नेता गठजोड़...' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद महेन्द्र व टिप्पर का सारा प्लान चौपट हो गया था।

अपनी इसी तैनाती के दौरान महेन्द्र शर्मा ने अपने ड्राइवर के माध्यम से, सेक्टर 8 में सड़क किनारे छतरी लगा कर बीमा पॉलिसी बेचने वाले से 500 रुपये प्रति दिन तय कर लिया। दुखी छतरी वाले ने विजिलेंस वालों से सेटिंग करके जब एक सप्ताह के 3500 रुपये थाने में आकर मुहर्रर हवलदार को दिये तो वह पकड़ा गया मुफ़्त में। तत्कालीन सीपी सुभाष यादव ने सारे खेल को समझने के बावजूद एसएचओ को कड़ी सज़ा देने के बजाय केवल लाइन हाज़िर करने तक में ही टाल दिया। उच्चाधिकारियों की ऐसी दरिया-दिल्ली एवं उदारता भ्रष्टाचारियों को और बड़ी-बड़ी डकैतियां मारने के लिये प्रोत्साहित करती है। उक्त दो उदाहरणों के अतिरिक्त इस तरह के अनेकों कारनामों से 'सुसज्जित' महन्द्र शर्मा दोनों विधायकों को रास आना ही था, सो आ रहा है। लेकिन इसके परिणाम क्या निकलेंगे?

ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस व अन्य अधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ही ग़लत काम करते हैं; इसलिये उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त कर दिया जाय। लोकतंत्र में अफ़सरशाही पर अंकुश रखने के लिये ही जनता के प्रतिनिधियों को अपार शक्तियां संविधान द्वारा दी गयी हैं। परन्तु इन शक्तियों का सदुपयोग होने की बजाय दुरूपयोग ही होता नज़र आता है। आजकल तमाम नेता अपनी पसंद के अफ़सरों को केवल इसलिये तैनात कराते हैं। ताकि वे उनके इशारों पर नाच कर उनकी दुकानदारी को बढवा सकें। आज देश भर में कानून एवं व्यवस्था तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था का जो जनाजा निकला पड़ा है उसके पीछे ऐसे ही राजनेताओं का योगदान है। इन्हें सही काम करनेवाला तो कोई अधिकारी रास आता ही नहीं।